Date ____
Page ____

## शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कमियाँ —

इस विधेयक की आलोचना में जो बातें कही जा रही हैं जो इस प्रकार हैं।

(i) अधिनियम में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गयी है जबकि समान शिक्षा लाने पर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ii) मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अन्तर्गत सिर्फ 25 फीसदी सीटों पर ही समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों को दाखिला मिलेगा।

(iii) मुफ्त शिक्षा की बात एक धोखा है क्योंकि बजट का प्रावधान नहीं है।

(iv) इसमें निःशुल्क शिक्षा एवं शिक्षण सामग्री से लेकर सम्पूर्ण शिक्षा का क्रियान्वयन कैसे हो इसकी बात नहीं है।

इन आलोचना के पश्चात भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एक संजीवनी बनकर आधुनिक शिक्षा में आया है। बस इस ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन की है।

# माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण
(Universalization of Secondary Education)

## माध्यमिक शिक्षा (Secondary Education) –

माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के मध्य सेतु का कार्य करती है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्तर है क्योंकि इस स्तर पर पढ़ने वाले छात्र किशोरावस्था के होते हैं यहीं से छात्र जीवन जीने की कला को सीखते हैं।

यद्यपि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुमूल्य परिवर्तन हुये हैं लेकिन माध्यमिक शिक्षा कुछ समय पहले तक कुल मिलाकर गतिहीन तथा अपरिवर्तित रही है।

## भारत में माध्यमिक शिक्षा का स्थान –
(Status of Secondary Education in India)

संवैधानिक प्रतिबद्धता के कारण सभी प्रयास 6 से 14 वर्ष (प्राथमिक शिक्षा) के लिए किए गये हैं। सर्वशिक्षा अभियान (SSA) भी सम्पूर्ण प्राथमिक शिक्षा की बात करता है। माध्यमिक शिक्षा कभी भी चर्चा का विषय नहीं रही है।

→ माध्यमिक स्तर पर समग्र दृष्टिकोण इस प्रकार है —

(i) 1950-51 से 1999-2000 के दौरान माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 74 हजार से बढ़कर 1 लाख 14 हजार हो गयी है।

(ii) इन्हीं वर्षों की तुलना में शिक्षकों की संख्या 1 लाख 27 हजार से बढ़कर 11 लाख 20 हजार हो गयी है।

(iii) बालिका नामांकन का प्रतिशत 13% से बढ़कर 38% हो गया है।

(iv) माध्यमिक शिक्षा में आवंटित धनराशि 20 करोड़ रुपये से नौवीं योजना में 2600 करोड़ हो गयी है।

इन सब प्रगति के बावजूद सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य तब तक नहीं प्राप्त किया जा सकता जब तक कि सार्वभौमिक प्राथमिक नामांकन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता।

# माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के मुद्दे :-

(Issues of Universalisation of Secondary Education).

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा का संख्यात्मक विकास जिस गति से हुआ है उसके परिणाम स्वरूप उसकी गुणवत्ता में शनैः शनैः कमी आती गयी। विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझावों के फलस्वरूप आज भी माध्यमिक शिक्षा शिक्षा व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है। आज भी समस्याओं से ग्रसित माध्यमिक शिक्षा की समस्या इस प्रकार है —

(i) माध्यमिक शिक्षा के सामान्य मुद्दे।
(General Issues of Secondary Education)

(ii) शिक्षा के व्यवसायीकरण के मुद्दे (Issues of Vocationalisation of Education)

(iii) माध्यमिक शिक्षा के आर्थिक मुद्दे।
(Issues of Economics of secondary Education)

(iv) शैक्षिक अवसरों की समानता से सम्बन्धित मुद्दे।
(Issues Related to Equality of Educational opportunity)